भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 461
जिसका उत्तर 23 जुलाई, 2025 को दिया जाना है ।
1 श्रावण, 1947 (शक)

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में सामान्य सेवा केंद्र

461. श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में स्थापित सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) की संख्या कितनी है;

(ख) उक्त केंद्रों का प्रबंधन करने वाली ग्राम स्तरीय महिला उद्यमियों (वीएलई) का प्रतिशत कितना है;

(ग) सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीडीआईएसएचए) के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) कौशल भारत कार्यक्रम के अंतर्गत आईटी कौशल में प्रशिक्षित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से जुड़े युवाओं की संख्या कितनी है; और

(ड.) दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में डिजिटल अंतर को पाटने के लिए क्या उपाय अपनाए गए हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से **(ङ)** : भारत सरकार ने नागरिक केन्द्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी) स्थापित करने की परियोजना शुरू की है। ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) को सीएससी स्थापित करने का अधिकार दिया गया है।

अब तक की स्थिति के अनुसार, अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी) बहुल क्षेत्रों में कुल 2.92 लाख सीएससी स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल इन क्षेत्रों में लगभग 10% सामान्य सेवा केन्द्रों का प्रबंधन महिलाओं द्वारा किया जा रहा है।

सरकार ने डिजिटल साक्षरता सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीडीआईएसएचए) शुरू किया। इसके तहत 6 करोड़ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लक्ष्य की तुलना में, देशभर में 6.39 करोड़ व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया।

यह सुनिश्चित किया गया था कि अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) जैसे समाज के सीमांत वर्गों को इस योजना के तहत शामिल किया गया है।अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित 1.17 करोड़ से अधिक व्यक्तियों, अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित 56 लाख से अधिक व्यक्तियों और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय से संबंधित 2.55 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है।

कौशल भारत कार्यक्रम के तहत, अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के 2.29 लाख से अधिक व्यक्तियों, 89 हजार से अधिक अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों और 38 हजार से अधिक अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है।

भारतनेट कार्यक्रम के तहत 2.14 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड के साथ सेवा के लिए तैयार किया गया है। विभिन्न योजनाओं के तहत, 4जी कनेक्टिविटी का 40 हजार (लगभग) गांवों में विस्तार किया जा रहा है।

*****